गए "धरने"/"की गई रिले भूख हड़ताल" से है जो जे0 के0 जूट मिल्स मजदूर पंचायत, कानपुर, और कानपुर जूट उद्योग पंचायत, जूट मजदूर कांग्रेस आदि के संयुक्त मोर्चे के कहने पर यह धरना / रिले भूख हड़ताल अन्य बातों के साथ-साथ कानपुर जूट उद्योग लिमिटेड का सरकार द्वारा प्रबन्ध-संभालने से सम्बन्धित उनकी मांग के समर्थन में की गई थी। उद्योग मंत्रालय इस यूनिट को दोबारा खुलवाने के लिए कार्यवाही पर विचार कर रहा है।

हिन्दी में तार

4392. श्री सुखेन्द्र सिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन नगरों के नाम क्या हैं जिनमें डाक व तार विभाग ने हिन्दी सेवा उपलब्ध की है ;

(ख) 1977 और 1978 में इस सेवा का लाभ उठाने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है ;

(ग) क्या यह सच है कि इस सेवा में तथा अंग्रेजी-हिन्दी और हिन्दी-अंग्रेजी के समानार्थक शब्द बताने के कार्य में लगे व्यक्ति हिन्दी में पूरी तरह अर्हता प्राप्त नहीं हैं और उत्तर देने से पूर्व उन्हें शब्दकोष देखना पड़ता है जिसके परिणामस्वरूप किसी शब्द का समानार्थक शब्द बताने में बहुत समय लग जाता है और कभी कभी तो वे उत्तर दे नहीं पाते;

(घ) क्या पूरी तरह से अर्हताप्राप्त व्यक्ति नियुक्त करना उपयुक्त नहीं होगा जो कि प्रश्नों का शीघ्र उत्तर दे सकें ताकि इस सेवा को अधिक लाभदायक बनाया जा सके ; और

(ङ) इस बारे में सरकार का विचार क्या सुधार करने का है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय): (क) देश में कुल 20,870 तारघरों में से करीब 9,800 तारघरों में देवनागरी लिपि में तार भेजने की सेवा उपलब्ध है। जिन शहरों में यह सेवा उपलब्ध है उनके नामों की सूची संकलित की जा रही है जो सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) इस सेवा का लाभ उठाने वाले व्यक्तियों की संख्या का कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है।

तथापि, 1977 और 1978 में देवनागरी में बुक किये गए तारों की संख्या इस प्रकार है :-

वर्ष	देवनागरी में बुक किए गए तारों की संख्या
1977	15,16,457
1978 (30-11-78 तक)	18,78,540 (लगभग)

(ग) जी नहीं। देवनागरी सेवा में प्रशिक्षित कर्मचारियों को आमतौर पर इस सेवा के लिए लगाया जाता है। तथापि, ठीक-ठीक पर्यायवाची शब्द सुनिश्चित करने के लिए कभी-कभी शब्दकोषों का संदर्भ आवश्यक हो जाता है।

(घ) और (ङ). कांउटरों पर यथासंभव अर्हताप्राप्त और प्रशिक्षित कर्मचारियों को लगाया जाता है ताकि वे जनता के प्रश्नों का समुचित रुप से उत्तर दे सकें।

Fair Rent Committee

4393. SHRI R. K. MHALGI: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether there is any such committee named as "Fair Rent Committee" in postal Department;

(b) if so, the details of composition, functions and jurisdiction of this committee;

(c) whether such committee exists in the district of Thana (Maharashtra) and the account of work it had performed during a period of last two years; and

(d) whether this committee could obtain any accommodation for post fairs in the district during last one year; if not the efforts made?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI): (a) Yes, Sir.

(b) In fact, there are two committees —one is called the Local Assessment Committee. It consists of the Divisional Superintendent of Post Offices and an Assistant Engineer of the P&T Civil

Wing nominated by the Head of the Circle. This Committee is constituted to assess the fair rent of buildings whose rent exceeds the powers of Divisional Officer but is less than Rs. 2,000 p.m. This Committee submits its recommendations to the Director Postal Services who takes the final decision in consultation with the Internal Financial Adviser. The other Committee is called the Circle Assessment Committee which is constituted to assess the rent of the buildings whose rent is Rs. 2,000 or more p.m. This Committee consists of one Director, Postal Services, Internal Financial Adviser and one Executive Engineer, P&T Civil Wing nominated by the Head of the Circle. This Committee submits its report to the Head of the Circle who takes the final decision.

(c) The Circle Committee examined four offers of buildings in District Thana (Maharashtra), during the last two years. Two buildings were taken on rent as a result of the work of the Committee.

(d) Presumably the phrase "post fairs" is a misprint for "post offices" If so, the reply is one.

तमिलनाडु में प्रति व्यक्ति चिकित्सा व्यय

4394. **डा० महादीपक सिंह शाक्य :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री प्रति व्यक्ति चिकित्सा व्यय के बारे में 6 अप्रैल, 1978 के तारांकित प्रश्न संख्या 626 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1974-75 के दौरान तमिलनाडु में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार ने 9 रु० 81 पै० प्रति व्यय किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 1976-77 और 1977-78 के दौरान उसमें वृद्धि करने का प्रस्ताव था ;

(ग) यदि हां, तो कितना और क्या सरकार अब तक किए गए प्रति व्यक्ति व्यय के बारे में सन्तुष्ट है ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या अन्य देशों से सहायता प्राप्त करने का सरकार का विचार है और यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं जिनके साथ इस बारे में बातचीत की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) से (ग). राज्य और केन्द्र दोनों सरकारों द्वारा किए गए प्लान और नान-प्लान खर्च के आधार पर प्रति व्यक्ति व्यय 9.81 रुपए था। तमिलनाडु में स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रति व्यक्ति खर्च जो 1975-76 में 10.94 रुपए था वह 1976-77 में बढ़ कर 14.29 रुपए हो गया। वर्ष 1977-78 के खर्च के आंकड़े अभी संकलित किए जाने हैं।

केन्द्र को और राज्य की सरकारें तमिलनाडु में लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ करने की स्थिति में सुधार लाने के लिए भरपूर प्रयास कर रही हैं और इस राज्य सरकार को विभिन्न राज्य योजनाओं और केन्द्र प्रायोजित योजनाओं को कार्यन्वित करने के लिए योजना आयोग द्वारा स्वीकृत परिव्यय के अनुसार सहायता की जा रही है।

तमिलनाडु में स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर 1976-77 में जहां 616.23 लाख रुपए का योजना खर्च आया था वहां वह 1977-78 में बढ़ कर 638.62 लाख रुपए हो गया।

(घ) सरकार किसी भी राज्य विशेष के लिए विदेशी सहायता नहीं मांग रही है। वैसे, दूसरे देशों ने मलेरिया नियंत्रण, अन्धता निवारण, चिकित्सा शिक्षा को नया रुप देने आदि जैसी हमारी कुछेक राष्ट्रीय योजनाओं के लिए सहायता दी है। किसी राज्य विशेष के स्वास्थ्य क्षेत्र के कार्यक्रम के लिए निश्चित किए गए समग्र योजना परिव्यय में सारे देशों तथा विदेशी साधनों दोनों की झलक मिलती है।

Modernisation of TISCO

4395. SHRI SUBHASH CHANDER BOSE ALLURI: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that TISCO has submitted a Rs. 440 crores programme to Government for modernisation of its units by 1983-84; and

(b) if so, what are the details in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI KARIA MUNDA): (a) A proposal for the modernisation of TISCO's Steel Plant at a capital cost of Rs. 118 crores has recently been received.